IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, January 2026
Impact Factor: 7.67

जनजातीय जीवन में विस्थापन के दौरान आजीविका एवं रोजगार पर प्रभाव : एक अध्ययन

डॉ. के.पी. अहिरवार
सेवानिवृत्त प्राचार्य
शासकीय ज्ञानचन्द्र श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह
जिला दमोह मध्यप्रदेश

प्रज्ञा सिंह
शोधार्थी समाजशास्त्र विभाग
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
छतरपुर मध्यप्रदेश

शोध सारांश -

यह शोध पत्र जनजातीय जीवन में विस्थापन के दौरान आजीविका एवं रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारत में विकास परियोजनाओं जैसे बाँध निर्माण, खनन, औद्योगिकीकरण तथा शहरी विस्तार के कारण बड़े पैमाने पर जनजातीय समुदायों का विस्थापन हुआ है। यह विस्थापन केवल भौगोलिक स्थानांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। विशेष रूप से आजीविका और रोजगार पर इसका प्रभाव अत्यंत गंभीर होता है, क्योंकि जनजातीय समुदायों की आर्थिक संरचना प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है। विस्थापन के पश्चात जनजातीय समुदाय अपनी पारंपरिक आजीविका जैसे कृषि, वन उत्पाद संग्रह, पशुपालन आदि से वंचित हो जाते हैं। नई परिस्थितियों में उन्हें असंगठित क्षेत्र में कम वेतन और अस्थायी रोजगार अपनाना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाती है। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि पुनर्वास नीतियाँ पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं हैं, जिससे विस्थापित समुदायों को दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पाती। अतः यह शोध पत्र समावेशी विकास, प्रभावी पुनर्वास नीति और कौशल विकास की आवश्यकता पर बल देता है।

e[; 'kCn %& विस्थापन, जनजातीय समुदाय, आजीविका, रोजगार, पुनर्वास, गरीबी, असंगठित क्षेत्र, विकास परियोजनाएँ

çLrkouk %&

भारत में जनजातीय समुदायों का जीवन प्रकृति के साथ गहरे संबंधों पर आधारित रहा है। वे सदियों से वन, भूमि और जल संसाधनों के माध्यम से अपनी आजीविका संचालित करते आए हैं। किंतु आधुनिक विकास की अवधारणा ने इस पारंपरिक जीवन पद्धति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, खनन तथा बड़े बाँधों के निर्माण ने लाखों जनजातीय परिवारों को उनके मूल निवास स्थानों से विस्थापित किया है।

विस्थापन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें केवल भौतिक स्थानांतरण ही नहीं बल्कि सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक आधार का विघटन भी शामिल होता है। जनजातीय समुदायों के लिए यह स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है क्योंकि उनकी आजीविका सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी होती है। जब वे इन संसाधनों से अलग होते हैं, तो उनकी

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, January 2026 Impact Factor: 7.67

पूरी आर्थिक व्यवस्था टूट जाती है। वर्तमान संदर्भ में यह आवश्यक हो जाता है कि विस्थापन के प्रभावों का गहन अध्ययन किया जाए, विशेषकर आजीविका एवं रोजगार के संदर्भ में, ताकि उचित नीतिगत हस्तक्षेप किए जा सकें और जनजातीय समुदायों का सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

'kks/k dk mís'; –

इस शोध का प्रमुख उद्देश्य जनजातीय जीवन में विस्थापन के दौरान आजीविका एवं रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि विस्थापन के कारण पारंपरिक आजीविका किस प्रकार प्रभावित होती है, रोजगार के स्वरूप में क्या परिवर्तन आते हैं, तथा पुनर्वास नीतियाँ इन प्रभावों को किस हद तक कम कर पाती हैं। साथ ही, यह अध्ययन विस्थापित जनजातीय समुदायों की आर्थिक स्थिति में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन करता है और उनके लिए संभावित समाधान प्रस्तुत करता है।

vkthfodk ,oa jkstxkj dk fo'ys"k.k &

जनजातीय समुदायों की आजीविका पारंपरिक रूप से प्रकृति आधारित होती है, जिसमें कृषि, वन उत्पाद संग्रह, शिकार, मछली पालन और पशुपालन प्रमुख गतिविधियाँ होती हैं। यह आजीविका प्रणाली आत्मनिर्भर और सामुदायिक सहयोग पर आधारित होती है। विस्थापन के कारण यह पूरी प्रणाली बाधित हो जाती है। विस्थापन के बाद सबसे पहला प्रभाव भूमि और वन संसाधनों के नुकसान के रूप में सामने आता है। भूमि जनजातीय जीवन का मुख्य आधार होती है, और इसके छिन जाने से वे अपनी पारंपरिक कृषि गतिविधियों को जारी नहीं रख पाते। इसी प्रकार वन उत्पादों से मिलने वाली आय भी समाप्त हो जाती है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा कमजोर हो जाती है। नई जगह पर रोजगार के अवसर सीमित और असंगठित होते हैं। अधिकांश विस्थापित लोग दिहाड़ी मजदूरी, निर्माण कार्य, खदानों में श्रम या घरेलू कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इन कार्यों में न तो स्थिरता होती है और न ही पर्याप्त आय। इसके अलावा, कार्य परिस्थितियाँ भी असुरक्षित होती हैं, जिससे उनका शोषण होता है।

महिलाओं के संदर्भ में स्थिति और भी गंभीर होती है। पारंपरिक समाज में महिलाएँ आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, किंतु विस्थापन के बाद उनके रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। उन्हें असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता कम हो जाती है। युवा वर्ग के लिए रोजगार के अवसरों की कमी उन्हें पलायन के लिए मजबूर करती है। वे शहरों की ओर जाते हैं और वहाँ अस्थायी कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इससे सामाजिक विघटन और पारिवारिक संरचना पर भी प्रभाव पड़ता है।

विस्थापन का प्रभाव केवल रोजगार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी पड़ता है। आय के अभाव में लोग पर्याप्त भोजन नहीं प्राप्त कर पाते, जिससे कुपोषण की समस्या बढ़ती है। शिक्षा के अवसर भी प्रभावित होते हैं, जिससे अगली पीढ़ी का विकास बाधित होता है। पुनर्वास नीतियाँ इस समस्या को कम करने का प्रयास करती हैं, किंतु उनका कार्यान्वयन अक्सर कमजोर होता है। मुआवजा अपर्याप्त होता है और रोजगार के स्थायी अवसर प्रदान नहीं किए जाते। इसके कारण विस्थापित समुदाय आर्थिक रूप से कमजोर बने रहते हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, January 2026 Impact Factor: 7.67

tutkrh; vkthfodk dk ikjifjd Lo:Ik &

जनजातीय समुदायों की आजीविका मुख्यतः प्रकृति पर आधारित होती है। वे शिकार–संग्रह, झूम कृषि, वन उत्पादों का संग्रह, पशुपालन तथा लघु कृषि जैसे कार्यों में संलग्न रहते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था नकद आधारित न होकर विनिमय प्रणाली पर आधारित होती है। वन से प्राप्त उत्पाद जैसे महुआ, तेंदूपत्ता, शहद, गोंद आदि इनके जीवन का आधार होते हैं।

इन समुदायों में श्रम विभाजन सरल एवं सामुदायिक होता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य आर्थिक गतिविधियों में योगदान करते हैं। महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे वन उत्पाद संग्रह, कृषि कार्य तथा घरेलू अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी निभाती हैं। इस प्रकार जनजातीय आजीविका एक समेकित एवं आत्मनिर्भर प्रणाली होती है, जो पर्यावरणीय संतुलन के साथ संचालित होती है।

foLFkkiu d dkj.k &

जनजातीय विस्थापन के प्रमुख कारणों में विकास परियोजनाएँ सबसे महत्वपूर्ण हैं। बड़े बाँध जैसे नर्मदा घाटी परियोजना, खनन कार्य, औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना तथा शहरी विस्तार ने लाखों जनजातीय लोगों को विस्थापित किया है। इसके अतिरिक्त वन संरक्षण नीतियाँ भी कभी–कभी इन समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर देती हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अक्सर जनजातीय समुदायों की सहमति या उनकी सांस्कृतिक आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया जाता है। परिणामस्वरूप वे अपने ही संसाधनों से बेदखल हो जाते हैं। यह विस्थापन अक्सर अनैच्छिक होता है, जिससे उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

foLFkkiu dk vkthfodk ij çHkko &

विस्थापन के बाद जनजातीय समुदाय अपनी पारंपरिक आजीविका से वंचित हो जाते हैं। भूमि, वन और जल जैसे संसाधनों की उपलब्धता समाप्त हो जाती है, जिससे उनकी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था टूट जाती है। वे कृषि, वन उत्पाद संग्रह या पशुपालन जैसे पारंपरिक कार्यों को जारी नहीं रख पाते। नई जगह पर उन्हें वैकल्पिक आजीविका के साधन नहीं मिल पाते, जिससे वे आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं। कई बार उन्हें अस्थायी मजदूरी या दिहाड़ी कार्यों पर निर्भर होना पड़ता है, जो न तो स्थायी होते हैं और न ही पर्याप्त आय प्रदान करते हैं। इस प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आती है और वे गरीबी के चक्र में फँस जाते हैं।

jkstxkj dk Lo:i esa ifjorZu &

विस्थापन के बाद रोजगार के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। पारंपरिक रोजगार से हटकर जनजातीय लोग शहरी या औद्योगिक क्षेत्रों में कम वेतन वाले कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इनमें निर्माण कार्य, ईंट भट्टे, खदान मजदूरी तथा घरेलू काम शामिल हैं। यह परिवर्तन न केवल आर्थिक अस्थिरता लाता है, बल्कि कार्य की प्रकृति भी शोषणकारी होती है। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ तथा सामाजिक सुरक्षा का अभाव झेलना पड़ता है। इसके अलावा, उनके पास आवश्यक कौशल एवं शिक्षा की कमी होने के कारण वे बेहतर रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

efgykvk ,o detkj oxk ij çHkko &

विस्थापन का प्रभाव महिलाओं एवं कमजोर वर्गों पर अधिक गंभीर होता है। पारंपरिक समाज में महिलाओं की आर्थिक भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु विस्थापन के बाद वे रोजगार के अवसरों से वंचित हो जाती हैं। कई बार उन्हें घरेलू कामगार या असंगठित क्षेत्र में काम करना पड़ता है, जहाँ शोषण की संभावना अधिक होती है। बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है, क्योंकि विस्थापन के कारण स्कूल छूट जाते हैं या नई जगह पर शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं। इससे बाल श्रम की समस्या भी बढ़ती है। वृद्ध एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्थिति और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि उनके लिए रोजगार के अवसर सीमित होते हैं।

[kk| lqj{kk ,o xjhch ij çHkko &

विस्थापन के कारण खाद्य सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। पहले जहाँ जनजातीय समुदाय अपने भोजन का अधिकांश भाग स्वयं उत्पन्न करते थे, वहीं अब उन्हें बाजार पर निर्भर होना पड़ता है। आय की कमी के कारण वे पर्याप्त भोजन नहीं खरीद पाते, जिससे कुपोषण की समस्या बढ़ती है। गरीबी का स्तर भी बढ़ता है, क्योंकि स्थायी रोजगार के अभाव में उनकी आय अस्थिर रहती है। कई परिवार कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर होते जाते हैं।

iquokl ,o ljdkjh uhfr;k &

सरकार द्वारा विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए विभिन्न नीतियाँ बनाई गई हैं, जैसे भूमि के बदले भूमि, मुआवजा, रोजगार के अवसर तथा आवास सुविधाएँ। 2013 के तहत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, इन नीतियों का कार्यान्वयन अक्सर प्रभावी नहीं होता। मुआवजा अपर्याप्त होता है, रोजगार के अवसर सीमित होते हैं और पुनर्वास स्थल पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है। इससे विस्थापित समुदायों की समस्याएँ और बढ़ जाती हैं।

lkekftd iwth ,o lkL—frd çHkko &

आजीविका एवं रोजगार के साथ–साथ सामाजिक पूंजी भी प्रभावित होती है। विस्थापन के कारण समुदाय बिखर जाते हैं, जिससे उनके सामाजिक संबंध कमजोर हो जाते हैं। पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं सांस्कृतिक प्रथाएँ धीरे–धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह सांस्कृतिक विघटन उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है, जिससे वे असुरक्षा एवं पहचान संकट का सामना करते हैं।

fu"d"k &

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय जीवन में विस्थापन का प्रभाव अत्यंत व्यापक और गहरा होता है, विशेष रूप से आजीविका एवं रोजगार के क्षेत्र में। विस्थापन के कारण पारंपरिक आर्थिक संरचना टूट जाती है और जनजातीय समुदाय असंगठित एवं अस्थायी रोजगार पर निर्भर हो जाते हैं। इससे उनकी आय में कमी आती है और वे गरीबी के चक्र में फँस जाते हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि वर्तमान पुनर्वास नीतियाँ पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं हैं और उन्हें अधिक समावेशी एवं व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो यह समस्या और गंभीर हो सकती है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, January 2026
Impact Factor: 7.67

l>ko &

इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि विकास परियोजनाओं की योजना बनाते समय जनजातीय समुदायों की सहमति और भागीदारी सुनिश्चित की जाए। पुनर्वास नीतियों को अधिक प्रभावी बनाया जाए और उन्हें भूमि, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से विस्थापित लोगों को नए रोजगार के लिए तैयार किया जाए। इसके अलावा, स्थानीय संसाधनों पर उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। गैर–सरकारी संगठनों और सामुदायिक संस्थाओं की भागीदारी भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो सकती है।

lUnHk xUFk lph &

1. सेर्निया, माइकल एम. (1997). विस्थापित जनसंख्या के पुनर्वास के लिए जोखिम एवं पुनर्निर्माण मॉडल। वर्ल्ड डेवलपमेंट, 25(10), 1569–1587।
2. सेर्निया, माइकल एम. (2000). विस्थापन, जोखिम और पुनर्निर्माण, एक वैचारिक रूपरेखा। विष्व बैंक, वाशिंगटन डी.सी. स्कडर, थॉमस (2005). बड़े बाँधों का भविष्य। अर्थस्कैन प्रकाशन।
3. फर्नांडीस, वाल्टर (2007). भारत में विकास और विस्थापन। इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली।
4. फर्नांडीस, वाल्टर, एवं थुकराल, ई. जी. (1989). विकास, विस्थापन और पुनर्वास। इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट।
5. माथुर, एच. एम. (2006). भारत में पुनर्वास प्रबंधन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. डाउनिंग, थॉमस ई. (2002). खनन–प्रेरित विस्थापन और नई गरीबी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट।
7. परासुरामन, एस. (1999). विकास की दुविधारू भारत में विस्थापन। मैकमिलन प्रकाशन।
8. बाविस्कर, अमिता (2004). नदी के भीतररू विकास और जनजातीय संघर्ष। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. टर्मिन्स्की, बोगुमिल (2013). विकास–प्रेरित विस्थापनरू सिद्धांत और व्यवहार। कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस।
10. विश्व बैंक (2001). अनैच्छिक पुनर्वास नीति। विष्व बैंक।
11. भारत सरकार (2013). भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013। नई दिल्ली।
12. सेर्निया, माइकल एम. (2008). मुआवजा एवं लाभ साझा करने की नीतियाँ। विश्व बैंक।
13. कोल्सन, एलिजाबेथ (1971). पुनर्वास के सामाजिक परिणाम।
14. ओलिवर–स्मिथ, एंथनी (2009). विकास और विस्थापन।
15. द्विवेदी, राजेश (2002). विकास–प्रेरित विस्थापन के मॉडल और विधियाँ। डेवलपमेंट एंड चेंज जर्नल।
16. कोठारी, सुनील (1996). विकास और पर्यावरणीय स्थिरता।
17. पाडेल, फेलिक्स, एवं दास, समीर (2010). धरती से बेदखलीरू खनन और जनजातीय जीवन। ओरिएंट ब्लैकस्वान।
18. योजना आयोग (2008). जनजातीय क्षेत्रों में विकास की चुनौतियाँ। नई दिल्ली।
19. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (2015). आदिवासी रोजगार प्रवृत्तियाँ।